जी जयलाल...अपीलकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य...प्रतिवादी

(2013 की सिविल अपील संख्या 4665)

29 मई, 2013

[डॉ. बी. एस. चौहान और दीपक मिश्रा, जे. जे.]

सेवा कानून:

चयन& पैनल वरीयता नहीं दर्शा रहा& प्रभाव& ऑल इंडिया रेडियो के सामान्य निदेशक पद समिति द्वारा अपीलाॅंट का एसएल नं 01 पर नाम के साथ तीन व्यक्तियों के नाम के पैनल की अनुशंसा की गयी। पूछा जाने पर चयन समिति ने पश्चात्वर्ती क्रम में अभ्यर्थीयों का नाम शाॅर्टलिस्ट किया व वरीयता के क्रम में अनुशंसा की। प्रतिवादी सं 4 को क्रमांक 1 पर रखा गया। आयोजित पैनल द्वारा विशेष रूप से यह नहीं बताया गया कि अनुशंसा मैरिट के क्रम में थी या वरीयता के क्रम में जैसा कि पूर्व में निर्धारित किया गया था। इसके विपरीत बोर्ड ने जो नाम भेजे थे उसी क्रम में रखे गये जो कि विचारार्थ विभाग द्वारा अनुशंसा किये गये थे। आगामी रूप से जो नाम रखे गये थे वे वरीयता क्रम में जानबूझकर रखे गये थे। तीन सदस्यो के स्थानापन्न हो जाने के बाद भी पहले के

बहुमत में कोई फर्क नहीं पडा और उन्होने प्रतिवादी नं. 04 को वरीयता दी। इस प्रकार इसमें कोई लकुना नहीं है कि समिति के तीन मैंबर्स नामों को वरीयता देने में शोर्टलिस्ट करने में शामिल थे। कोई कानूनी द्वेष का तत्व विद्यमान नहीं है।

चयन-वरीयता के क्रम में अनुशंसा-वरीयता शब्द- का अर्थ।

ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में महानिदेशक के पदों को भरने के लिए क्रमशः 20.10.2010 और 20.12.2010 को विज्ञापन जारी किए गए थे। उक्त दो पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के लिए प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए अपीलकर्ता और चौथे प्रतिवादी सहित नौ व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की गई थी। चयन समिति की सिफारिशें सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती द्वारा दिनांक 16.3.2011 के पत्र के माध्यम से भारत सरकार को भेज दी गई थीं। समिति ने दूरदर्शन के महानिदेशक पद के लिए तीन नाम और ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक पद के लिए दो व्यक्तियों के नाम, अपीलकर्ता और चौथे प्रतिवादी के नाम भेजे। सिफ़ारिशें प्राप्त होने पर, प्रसार भारती के विशेष कर्तव्य अधिकारी द्वारा चयन समिति के सभी सदस्यों को दिनांक 21.3.2011 का एक पत्र प्रसारित किया गया था।

अपीलकर्ता ने एक O.A को प्राथमिकता दी। न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांकित सिफारिशों को रद्द करने की मांग 21.3.2011 और एक निर्देश जारी करने की भी मांग की उत्तरदाताओं को दिनांकित 15.3.2011 सिफारिशों के अनुसार कार्य करना होगा और तर्क दिया कि वरीयता क्रम में उन्हें नंबर 1 पर रखा गया था महानिदेशक, ऑल इंडिया रेडियो के पद पर नियुक्ति हेतु ट्राइब्यूअल उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के मामले को स्वीकार नहीं किया।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

1.1. वैचारिक प्राथमिकता, मूलतः, इसका मतलब यह होगा कि सभी पहलू, अर्थात् योग्यता, उपयुक्तता, फिटनेस आदि समान होने पर प्राथमिकता दी जाती है कुछ अन्य उच्च योग्यता या अनुभव होना चाहिए, [पैरा 12] [878-जी]

सचिव, ए.पी. लोक सेवा आयोग बनाम वाई. वी. वी. आर. श्रीनिवासु/यू और अन्य 2003 (3) एससीआर 742 2003 (5) धारा 341- संदर्भित

1.2. मौजूदा मामले में, यह विवादित नहीं है कि दोनों उम्मीदवार पात्र थे। बैठक का कार्यवृत्त सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि तीन के पद हेतु विभागीय अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया महानिदेशक, ऑल इंडिया रेडियो. के नाम अपीलकर्ता और चौथे प्रतिवादी

को क्रम में रखा गया था क्रमशः क्रमांक 1 और 2। जब समिति ने अपनी सिफारिशें दी यह उन्हें भी उसी वरीयता में रखा पैराग्राफ 4 में प्रयुक्त भाषा में कहा गया है कि समग्र योग्यता और अनुभव के विचार को ध्यान में रखते हुए और सम्मान के साथ उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हुए, बोर्ड ने भारत सरकार को सिफ़ारिशें अग्रेषित करने का निर्णय लिया लेकिन यह विशेष रूप से यह नहीं बताया गया है कि बोर्ड द्वारा निर्धारित सिफ़ारिशें योग्यता के क्रम में या वरीयता के क्रम में थे। इसके विपरीत, यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि बोर्ड ने वही नाम रखे हैं जो विभाग द्वारा विचारार्थभेजे गये है। [पैरा 13] [879-डी-जी]

1.3. यह नहीं कहा जा सकता कि कोई गलत कार्य हुआ है, अपीलकर्ता को कोई कानूनी चोट पहुंचाने के लिए ऐसा किया। यह मानना कठिन है कि कोई भी कार्य उपेक्षा के लिए किया गया है या उसके कानूनी अधिकारों को हरण के लिए किया गया है Fks A ओएसडी द्वारा मूल रूप से बोर्ड को वरीयता क्रम में नाम शॉर्टलिस्ट करने की आवश्यकता gsrq कहा गया हैA बोर्ड के सदस्य वरीयता के अनुसार नाम दोहरा सकत था जो कि उन्होंने पहले सिफारिश की थीं । बोर्ड यह कह सकता था कि जो सिफारिशे पहले की गई थी वह पहले ही वरियता के क्रम में ही थी इसके बाद विचार-विमर्श करके जब इसे न्यायाधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया, इस प्रकार कानूनी द्वेष का कोई तत्व नहीं है. [पैरा 16] [881-ए-सी]

आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम गोवर्धनलाल पिट्टी 2003 (2) एससीआर 908 = 2003 (4) एससीसी 739; पश्चिम बंगाल राज्य एच इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम दिलीप कुमार रे 2006 (9) सीआर 554 2007 (14) एससीसी 568 और कलाभारती विज्ञापन वी. हेमर'ल्ट विमलनाथ नरीचानिया और · अन्य 2010 (10) एससीआर 971 = 2010 (9) एससीसी 43·, - संदर्भित

1.4. तीनों में से किसी भी पक्ष से कोई विवाद नहीं है क्योंकि कुछ को प्रतिस्थापित किया गया था कुछ सेवानिवृत्त हो गए और कुछ का कार्यकाल समाप्त हो गया जिन तीन सदस्यों को नियुक्त किया गया है, उनमें असहमतता नहीं है fD वैध रूप से नियुक्त किया गया है। समय के प्रवाह से, कुछ बोर्ड के सदस्यों को प्रतिस्थापित और अलग कर दिया गया कुछ बोर्ड के सदस्यों को शामिल किया गया. ट्रिब्यूनल ने इस पर विचार किया पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को बोर्ड के पास भेजना उचित है

गहन विचार विमर्श के बाद मामले को ध्यान में रखते हुए बैठक के कार्यवृत्त से यह स्पष्ट है कि बोर्ड के द्वारा प्राधिकार की अनुशंसा करते हुए विचार व्यक्त किया। इस प्रकार आगे साक्षात्कार आयोजित करना आवश्यक नहीं था प्राथमिकता के रूप में मिनटों में यह बिल्कुल स्पष्ट था कोई प्राथमिकता नहीं दी गई. अत: इसमें कोई दोष नहीं है की शॉर्ट-लिस्टिंग में भाग लेने वाले तीन सदस्य नाम और प्राथमिकता देना. इसके अलावा,

बहुमत पहले के सदस्य वहां थे और उन्होंने ई. दिया था चौथे प्रतिवादी के पक्ष में वरीयता और, इसलिए, तथ्यात्मक रूप से, इसने कोई भी कार्य नहीं किया होगा अंतर। [पैरा 17 और 19) [881-ई; 882-ई-एच; 883-ए-बी]

केस कानून संदर्भ: 1987 (1) एससीआर 1054 को अनुपयुक्त पैरा 9 माना गया

2003 (3) एससीआर 7 42 संदर्भित 2003 (2) एससीआर 908 पैरा 14 को संदर्भित करता है 2006 (9) पूरक। एससीआर 554 को पैरा 15 में संदर्भित किया गया है पैरा 15 का हवाला दिया गया 2010 (10) एससीआर 971 12 सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या. 2013 का 4665. के निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.02.2012 से सिविल रिट याचिका संख्या 61 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली 2012 का.

एम.एन. अपीलार्थी की ओर से कृष्णमणि, संजय कुमार पाठक।

पारस कुहाड़, एएसजी, विकास सिंह, स्वाति विजयवर्गीय, जितिन चतुर्वेदी, रेखा पांडे, डी.एस. महरा, राजीव शर्मा, साहिल भाईइक, उद्यम मुखर्जी, संकेत, दीपिका कालिया, एम.सी.ढींगरा, राजेश श्रीवास्तव प्रतिवादियों की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

दीपक मिश्रा, जे. 1. इस अपील में, की गर्भधारणशीलता आदेश दिनांक 17.2.2012 पीसी: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत WP. (सी)

दिनांक 30.11.2011 के आदेश की पुष्टि करते हुए 2012 की संख्या 61 डी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ द्वारा पारित, नई दिल्ली (संक्षेप में "द ट्रिब्यूनल") ओ.ए. में। 2011 का क्रमांक 1290 है iz'u fd;s x;s

02. तथ्य, जैसा कि उजागर किया गया है,ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में सामान्य निदेशक के पदों को भरने के लिए विज्ञापन 20.10.2010 और क्रमशः 20.12.2010 जारी किये गये

एक समिति अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रसार भारती बोर्ड का गठन किया गया,चयन समिति द्वारा साक्षात्कार gsrq अपीलकर्ता सहित नौ व्यक्तियों के नाम की अनुशंसा की गई थी। सदस्य(कार्मिक) द्वारा दिनांक 16.3.2011 के पत्र द्वारा भारत सरकार, प्रसार भारती. चयन समिति की सिफ़ारिश रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। समिति ने दूरदर्शन महानिदेशक का पद के लिए तीन नाम भेजे और दो अपीलकर्ता के नाम और चौथे प्रतिवादी , दिनांक 21.3.2011 द्वारा एक पत्र प्रसारित किया गया था सभी सदस्यों को प्रसार भारती में विशेष कर्तव्य अधिकारी चयन समिति के पत्र में उल्लेख किया गया था कि 15.3.2011 को आयोजित विशेष बैठक में, चयन बोर्ड ने उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद और सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पदों के लिए उम्मीदवारों के एक पैनल की सिफारिश करने का निर्णय लिया था, लेकिन नामों के अनुसार चयन बोर्ड

द्वारा अनुशंसित नामों को किसी विशेष वरीयता क्रम में नहीं रखा गया था, सरकार की इच्छा थी कि पैनल में नामों को वरीयता क्रम में रखा जाए।पत्र प्राप्त होने के बाद, बोर्ड द्वारा सर्कुलेशन के माध्यम से वरीयता क्रम में उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद, चयन समिति के प्रत्येक सदस्य ने अलग-अलग समर्थन के माध्यम से अपनी सिफारिशें दीं। नौ सदस्यों वाली चयन समिति के आठ सदस्यों ने महानिदेशक, ऑल इंडिया रेडियो के पद के लिए वरीयता क्रम में चौथे प्रतिवादी को क्रम संख्या 1 पर और अपीलकर्ता को क्रम संख्या 2 पर रखा। समिति के नौ में से पांच सदस्यों ने महानिदेशक के पद के लिए वरीयता क्रम में श्री त्रिपुरारी शरण को क्रम संख्या 1 पर, श्री राम सुभग सिंह को क्रम संख्या 2 पर और श्री एलडी मंडलोई को क्रम संख्या 3 पर रखा। दूरदर्शन. रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि चयन समिति के अधिकांश सदस्यों ने महानिदेशक, ऑल इंडिया रेडियो के पद के लिए चौथे प्रतिवादी को वरीयता क्रम में नंबर 1 पर और महानिदेशक, दूरदर्शन के पद के लिए श्री त्रिपुरारी शरण को रखा। . मालूम हो कि अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश दूरदर्शन के महानिदेशक पद के लिए भी की गई थी।

03. उस स्तर पर, अपीलकर्ता ने 21.3.2011 की सिफारिशों को रद्द करने की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल के समक्ष 2011 के ओए नंबर 1290 को प्राथमिकता दी और 15.3.2011 की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने की भी मांग की। ऐसी प्रार्थना

इसलिए की गई क्योंकि अपीलकर्ता का रुख यह था कि उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए वरीयता क्रम में नंबर 1 पर रखा गया था। ट्रिब्यूनल ने वरीयता क्रम में नाम रखने के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों को स्वीकार नहीं किया।

चयन समिति के निर्णय को बदलने में सरकार के किसी प्राधिकारी के कृत्य से संबंधित दुर्भावनापूर्ण दलील को भी स्वीकार नहीं किया गया। हालाँकि, ट्रिब्यूनल की राय थी कि 21.3.2011 को जो वरीयता क्रम तय किया गया है, वह सर्कुलेशन द्वारा तय नहीं किया जा सकता था और उक्त उद्देश्य के लिए प्रसार भारती बोर्ड (चयन समिति) की एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता थी और निर्णय लिया गया था। बोर्ड के सदस्यों के बीच उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद लिया जाना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण के चलते, ट्रिब्यूनल ने उत्तरदाताओं को उम्मीदवारों की योग्यता का क्रम निर्धारित करने के लिए बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि यदि बैठक के नतीजे से पहले के दृष्टिकोण का समर्थन होगा, तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के क्रम में बोर्ड की बैठक बुलाई गई और सर्कुलेशन द्वारा लिए गए निर्णय को दोहराया गया।

4. उक्त पुष्टि से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि ट्रिब्यूनल ने यह कहकर इस मुद्दे को बंद कर

दिया था कि यदि पहले के दृष्टिकोण की पुष्टि या समर्थन होगा, तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञात हो, जब ट्रिब्यूनल ने मूल आवेदन पर फैसला किया, तब तक तीन सदस्यों का कार्यकाल या तो सेवानिवृत्ति या कार्यकाल की समाप्ति के कारण समाप्त हो चुका था। उच्च न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि चूंकि बोर्ड के तीन नए सदस्यों ने उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं लिया है, इसलिए वे उम्मीदवारों की योग्यता के संबंध में सूचित दृष्टिकोण अपनाने की स्थिति में नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने से इनकार कर दिया कि यदि अपीलकर्ता ट्रिब्यूनल के निर्देश के अनुसार बुलाई गई बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय से व्यथित है, तो वह ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए खुला है। उच्च न्यायालय ने एकमात्र मुद्दे पर विचार किया कि क्या चयन समिति ने 15.3.2011 को हुई अपनी बैठक में अपीलकर्ता को ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के पद के लिए वरीयता क्रम में रखा था या नहीं। बैठक के विवरण पर गौर करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि सिफारिशों का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि जिस व्यक्ति का नाम नंबर 1 पर दिखाया गया था वह योग्यता के क्रम में पहले स्थान पर था। यह आरोप कि अपीलकर्ता को वैध दावे से वंचित करने के लिए 15.3.2011 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिफारिश को बदलने के लिए चयन समिति के सदस्यों को प्रभावित करने में सरकार में से किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, स्वीकार नहीं

किया गया। उच्च न्यायालय दुर्भावना के आरोप से निपटने के लिए आगे बढ़ा और राय दी कि चूंकि किसी भी सरकारी प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष उम्मीदवार के प्रति कोई पक्षपात दिखाने के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया था, इसलिए उक्त आरोप स्वीकार्य नहीं थे। इस आशय की कानूनी दुर्भावना की दलील कि सरकार ने प्रसार भारती बोर्ड को एक विशेष तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया था, उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया क्योंकि यह किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं था। इस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी।

5. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एमएन कृष्णमणि, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पारस कुहाड़, पांचवें प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह, चौथे प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री एमसी ढींगरा को सुना है। प्रतिवादी, श्री राजीव शर्मा और श्री राजेश श्रीवास्तव, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील थे।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कृष्णमणि ने मूल रूप से तीन तर्क उठाए हैं, अर्थात्,

(i) चयन समिति की सिफारिशों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि उसने वरीयता क्रम में नाम भेजे थे। वरिष्ठता, योग्यता और उपयुक्तता को ध्यान में रखा जा रहा था, लेकिन इसे बोर्ड द्वारा बदल दिया गया, जिसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था;

(ii) ट्रिब्यूनल द्वारा सर्कुलेशन के माध्यम से लिए गए निर्णय को रद्द करने के बाद, मामले पर उचित विचार-विमर्श द्वारा पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन चयन समिति के तीन सदस्य जिन्होंने उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं लिया था, उन्हें बदल दिया गया था और इसलिए, बोर्ड का निर्णय ख़राब हो गया है;

और (iii) सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा निर्णय को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है और यह कानूनी दुर्भावना के समान है जो चयन को कानून की दृष्टि से असुरक्षित बनाता है।

7. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पारस कुहाड़ ने प्रस्तुत किया है कि सिफारिशों में योग्यता के आधार पर किसी प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया गया है और इसलिए, उस संबंध में धारणा बिल्कुल गलत है। उनका आग्रह है कि विशेष कर्तव्य अधिकारी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि उनकी समझ के अनुसार, कोई प्राथमिकता नहीं थी और सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था, जिसके लिए समिति को किसी विशेष तरीके से कोई कार्य करने की आवश्यकता थी और इसलिए, किसी कानूनी दुर्भावना का सुझाव देने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष चयन की कार्यवाही प्रस्तुत की है।

8. चौथे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ढींगरा ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल अभेद्य और

बचाव योग्य है और इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. पांचवें प्रतिवादी, महानिदेशक, दूरदर्शन की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने प्रस्तुत किया कि उनकी सेवानिवृत्ति या कार्यकाल की समाप्ति और संविधान के गठन के कारण वरीयता द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई थी और तीन सदस्यों की अनुपलब्धता थी। तीन नए सदस्यों को शामिल करने से बोर्ड का चयन प्रभावित नहीं होगा। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, उन्होंने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 4(2) पर भरोसा किया है और बीके श्रीनिवासन और अन्य बनाम राज्य मामले में निर्णय के लिए हमारी सराहना की है। कर्नाटक और अन्य के [1]।

10. उपरोक्त प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, हम दिनांक 15.3.2011 की बैठक के कार्यवृत्त का उल्लेख करेंगे। मिनटों का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

"2. बोर्ड ने महानिदेशक, ऑल इंडिया रेडियो के पद के लिए निम्नलिखित अधिकारियों (जिन्होंने साक्षात्कार के संबंध में सूचना का जवाब दिया) का साक्षात्कार लिया: -

मैं। श्री जी. जयलाल ii. श्री एलडी मंडलोई iii. श्री अशोक जेलखानी

3. बोर्ड ने महानिदेशक, दूरदर्शन के पद के लिए निम्नलिखित अधिकारियों (जिन्होंने साक्षात्कार के संबंध में सूचना का जवाब दिया) का साक्षात्कार लिया: -

बाहरी उम्मीदवार

i) श्री सुनील कुमार सिंह

ii) श्री राम सुभग सिंह

iii) श्री अनिल कुमार अग्रवाल

iv) श्री मनोज कुमार पांडा

v) श्री जगमोहन सिंह राजू

vi) श्री त्रिपुरारी शरण विभागीय उम्मीदवार

i) श्री जी जयलाल

ii) श्री एलडी मंडलोई

iii) श्री अशोक जेलखानी

4. समग्र योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए और उपयुक्तता के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने भारत सरकार को सिफारिशें अग्रेषित करने का निर्णय लिया, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

दूरदर्शन के महानिदेशक पद के लिए

1. श्री. एलडी मंडलोई

2. श्री. त्रिपुरारी शरण

3. श्री. रामसुभग सिंह महानिदेशक, आकाशवाणी के पद के लिए

1. श्री. जी जयलाल

2. श्री. एलडी मंडलोई"

11. यह तर्क दिया गया है कि यह वरीयता क्रम में एक सिफारिश थी। फ़ाइल को देखने पर पता चलता है कि सिफ़ारिशें भेजे जाने के बाद, ओएसडी ने एक पत्र प्रसारित किया था जिसमें कहा गया था कि बोर्ड ने योग्यता या वरीयता के क्रम में नाम नहीं भेजे थे और इसलिए, यह आवश्यक था कि नाम संक्षिप्त किए जाएं। -वरीयता क्रम में सूचीबद्ध। रिकार्ड से यह भी स्पष्ट है कि चयन समिति के प्रत्येक सदस्य ने ओएसडी द्वारा प्रसारित प्रस्तावित निर्णय पर अलग-अलग अपनी अनुशंसा दी। चयन समिति के किसी भी सदस्य ने अपनी अनुशंसा देते समय यह नहीं बताया कि 15.3.2011 को हुई बैठक में बोर्ड ने योग्यता के क्रम में नामों की अनुशंसा की थी. यह भी ध्यान देने योग्य है कि सदस्यों में से एक, डॉ. जॉर्ज वर्गीस, जिन्होंने अपीलकर्ता को नंबर 1 पर रखने की सिफारिश की थी, ने यह भी उल्लेख नहीं किया था कि नाम पहले ही योग्यता की प्राथमिकता के क्रम में रखे गए थे। हमने केवल यह इंगित करने के लिए इसका उल्लेख किया है कि बोर्ड के सदस्यों ने उस परिप्रेक्ष्य में कार्यवृत्त को समझा था।

12. इस समय, हम यह बताना उचित समझते हैं कि योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर कब वरीयता दी जाती है। वैचारिक प्राथमिकता, मूल रूप से, इसका मतलब यह होगा कि सभी पहलू, अर्थात् योग्यता, उपयुक्तता, फिटनेस, आदि समान होने पर, किसी अन्य उच्च योग्यता या अनुभव आदि को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में, हम लाभ का उल्लेख कर सकते हैं सचिव, एपी लोक सेवा आयोग बनाम वाईवीवीआर श्रीनिवासुलु और अन्य में आदेश [2] जिसमें दो-न्यायाधीशों की पीठ ने वरीयता के बारे में कहा था। यद्यपि सिद्धांत एक विशेष नियम के संदर्भ में निर्धारित किया गया था, फिर भी हम लाभ के साथ उसी को पुन: प्रस्तुत करते हैं: -

> "जब भी, प्रतिस्पर्धा से जुड़े योग्यता प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाना है, और वरीयता देने के लिए किसी अतिरिक्त योग्यता या कारक के कब्जे की भी परिकल्पना की गई है, तो यह उन्हें दूसरों से आगे रखने के उद्देश्य से नहीं हो सकता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके आंतरिक मूल्य या सिद्ध पारस्परिक योग्यता और उपयुक्तता का विधिवत मूल्यांकन किया जाता है। चयन की ऐसी सभी प्रतिस्पर्धी योजनाओं के संदर्भ में वरीयता का मतलब केवल यह होगा कि अन्य चीजें गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से समान

होने पर, अतिरिक्त योग्यता वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी है।

13. मौजूदा मामले में, यह विवादित नहीं है कि दोनों उम्मीदवार पात्र थे। यदि बैठक के मिनट्स, जो हमने यहां पहले प्रस्तुत किए हैं, का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए, तो यह ध्यान देने योग्य है कि ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के पद के लिए तीन विभागीय उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था। अपीलकर्ता और चौथे प्रतिवादी के नाम क्रमशः क्रमांक 1 और 2 पर रखे गए थे। जब समिति ने सिफारिश की, तो उसने उन्हें भी उसी क्रम में रखा। मिनटों के पैराग्राफ 4 में इस्तेमाल की गई भाषा में कहा गया है कि समग्र योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए और उपयुक्तता के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने भारत सरकार को सिफारिशें भेजने का फैसला किया। लेकिन इसमें विशेष रूप से यह नहीं बताया गया है कि सिफारिशें योग्यता के क्रम में थीं या बोर्ड द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम में थीं। इसके विपरीत, यह इस तथ्य का सूचक है कि बोर्ड ने नामों को उसी क्रम में रखा है, जिस क्रम में विभाग ने विचार के लिए भेजा था। इस प्रकार, श्री कृष्णमणि का यह कहना कि नाम योग्यता या वरीयता के क्रम में भेजे गए थे, स्वीकार्यता के योग्य नहीं है।

14. तर्क का अगला पहलू यह है कि एक विशेष तरीके से निर्णय लेने में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। उक्त पहलू कानूनी द्वेष से जुड़ा हुआ है और इसलिए, दोनों पहलुओं से एक ही डिब्बे में निपटना आवश्यक है। हाईकोर्ट ने विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की ओर से दाखिल हलफनामे का हवाला देकर तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया है। विशेष कर्तव्य अधिकारी द्वारा 21.3.2011 को प्रसारित पत्र में, उन्होंने केवल सुझाव दिया था कि बोर्ड को वरीयता क्रम में उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने की आवश्यकता थी। संपूर्ण निर्णय बोर्ड पर छोड़ दिया गया। कोई सुझाव नहीं दिया गया. श्री कृष्णमणि ने बहुत निष्पक्षता से कहा है कि अपीलकर्ता का इरादा किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत दुर्भावना का आरोप लगाने का नहीं बल्कि कानूनी द्वेष का है क्योंकि उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने का सुझाव दिया गया था जो बिल्कुल अनावश्यक था। संक्षेप में, विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील यह है कि अधिकारियों की कार्रवाई कानून के अनुसार प्रामाणिक नहीं है। इस संदर्भ में, हम लाभ के साथ आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम गोवर्धनलाल पिट्टी [3] के फैसले का हवाला दे सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार फैसला सुनाया था: -

> " "कानूनी द्वेष" या "कानून में द्वेष" का अर्थ है "कानूनी बहाने के बिना किया गया कुछ"। दूसरे शब्दों में, "यह उचित या संभावित कारण के बिना गलत तरीके से और जानबूझकर किया गया कार्य है, और जरूरी नहीं कि यह

बुरी भावना और द्वेष से किया गया कार्य हो। यह दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा करने वाला एक जानबूझकर किया गया कृत्य है।" (शब्द और वाक्यांश कानूनी रूप से परिभाषित, तीसरा संस्करण, लंदन बटरवर्थ्स, 1989 देखें।)"

"जहां द्वेष को राज्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, यह कभी भी राज्य की ओर से व्यक्तिगत दुर्भावना या द्वेष का मामला नहीं हो सकता है। यदि कानूनी दृष्टि से यह दुर्भावना है, तो इसे एक ऐसे कृत्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो किसी परोक्ष या अप्रत्यक्ष उद्देश्य से किया गया है।"

15. इसी तरह का विचार पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम दिलीप कुमार रे [4] और कलाभारती एडवरटाइजिंग बनाम हेमंत विमलनाथ नरीचानिया और अन्य [5] में व्यक्त किया गया है ।

16. कानून के उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता को कोई कानूनी चोट पहुंचाने के लिए कोई गलत कार्य किया गया है। यह मानना कठिन है कि कोई भी कार्य उसके कानूनी अधिकारों की अवहेलना या उन्हें पराजित करने के लिए किया गया है। ओएसडी द्वारा जो कहा गया है वह मूल रूप से बोर्ड को वरीयता क्रम में नामों को संक्षिप्त करने की आवश्यकता है। बोर्ड के सदस्य यह दोहरा सकते

थे कि उन्होंने पहले वरीयता के अनुरूप नामों की सिफारिश की थी। हम सही ढंग से सोचने के इच्छुक हैं, उन्होंने यह नहीं कहा कि पहले से ही की गई सिफारिशें वरीयता के क्रम में थीं, बल्कि शुरुआत में संचलन द्वारा और जब इसे ट्रिब्यूनल द्वारा अलग कर दिया गया था, उसके बाद विचार-विमर्श द्वारा प्राथमिकता दी गई थी। इस प्रकार, कानूनी द्वेष से संबंधित प्रस्तुति, मूल आधार के बिना, खारिज कर दी जाती है।

17. विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क का अंतिम मुद्दा यह है कि तीन नए सदस्यों को शामिल करना जिन्होंने उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं लिया था, बोर्ड के निर्णय को रद्द कर देगा। उच्च न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया है और राय दी है कि यदि उक्त निर्णय पर आपत्ति जताने की आवश्यकता है, तो अपीलकर्ता के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना खुला है। किसी भी ओर से इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि तीन सदस्यों को प्रतिस्थापित करना पड़ा क्योंकि कुछ सेवानिवृत्त हो गए थे और कुछ का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अधिनियम की धारा 4 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। धारा 4 की उपधारा (1) और (2) इस प्रकार पढ़ें:-

> "4. अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति. – (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को, पदेन सदस्यों को छोड़कर, नामांकित सदस्य और निर्वाचित सदस्यों को एक समिति की सिफारिश

पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसमें शामिल हैं-

क) राज्य सभा का अध्यक्ष, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

बी) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 4 के तहत स्थापित भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष ; और

ग) भारत के राष्ट्रपति का एक नामांकित व्यक्ति।

(2) उप-धारा (1) के तहत नियुक्त समिति में किसी रिक्ति या उसके संविधान में किसी दोष के कारण किसी भी सदस्य की नियुक्ति अमान्य नहीं की जाएगी।

18. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) महानिदेशक (आकाशवाणी) और महानिदेशक (दूरदर्शन) (भर्ती) विनियम, 2001 का विनियमन 5 इस प्रकार है: -

"5. नियुक्ति प्राधिकारी: अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भर्ती बोर्ड के परामर्श के बाद निगम द्वारा की जाएगी।

19. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन तीन सदस्यों को नियुक्त किया गया है, वे वैध रूप से नियुक्त किए गए हैं। हालाँकि, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने बीके श्रीनिवासन (सुप्रा) में निहित "गंगा" खंड के

सिद्धांत की अवधारणा से प्रेरणा ली है, फिर भी इसे बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति के रूप में विज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं है। न ही सदस्य के रूप में उनके पद पर बने रहने पर सवाल उठाया जाता है। मामला थोड़ा अलग है. समय के साथ, बोर्ड के कुछ सदस्यों को हटा दिया गया और अलग-अलग सदस्यों को शामिल किया गया। ट्रिब्यूनल ने उचित विचार-विमर्श के बाद मामले पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को बोर्ड के पास भेजना उचित समझा। बैठक के मिनटों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि बोर्ड ने सिफारिश करने वाले प्राधिकारी द्वारा संपूर्ण विचार-विमर्श किया है, जैसा कि हम रिकॉर्ड से पाते हैं, और विचार व्यक्त किया है। इस प्रकार, वरीयता जानने के लिए आगे साक्षात्कार आयोजित करना आवश्यक नहीं था क्योंकि उस दिन मिनट बिल्कुल स्पष्ट थे कि कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी। इसलिए, हमें तीनों सदस्यों द्वारा नामों की शॉर्टलिस्टिंग में भाग लेने और वरीयता देने में कोई खामी नहीं दिखती। इसके अलावा, पहले के सदस्यों का बहुमत वहां था और उन्होंने चौथे प्रतिवादी के पक्ष में प्राथमिकता दी थी और इसलिए, तथ्यात्मक रूप से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार विश्लेषण करने पर, हमें इस विवाद में कोई योग्यता नजर नहीं आती।

20. उपरोक्त आधारिक कारणों को ध्यान में रखते हुए, अपील में कोई सार नहीं है और तदनुसार, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी स्वाति परेवा आर.जे.एस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।